

बरेली जिले में वित्तीय समावेशन का प्रभाव

डॉ.अंग्रेज सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
अर्थशास्त्र विभाग, उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।

पंकज कुमार वर्मा

शोधार्थी, अर्थशास्त्र, एम.जे.पी.आर.यू. बरेली, उत्तर प्रदेश।

Article Info

Volume 4 Issue 1

Page Number: 123-128

Publication Issue :

January-February-2021

Article History

Accepted : 02 Feb 2021

Published : 15 Feb 2021

सारांश— बरेली के लोगों को उनकी बचत और निवेश की जरूरत के लिए बैंकिंग शाखाओं तक पहुंच अच्छी है, लगभग 71 प्रतिशत लोगों की बैंको तक पहुंच है, परंतु बीमा योजना के बारे में वे लोग अभी अच्छी तरह से परिचित नहीं हैं इसलिए उनका ठीक प्रकार लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यह बीमा योजनाएं सुरक्षा हेतु परम आवश्यक है।
मुख्य शब्द— बरेली, जिला, वित्तीय, समावेशन, विकासीय, बैंक

विकासीय प्रायोजन की पहली मौलिक आवश्यकता है, वित्त की सर्वांगीण सुलभता। यही विकास को त्वरित व समावेशी बनाती है। अतः समावेशी विकास का लक्ष्य वित्तीय समावेशन में ही संभव है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, “वित्तीय समावेशन से अभिप्राय अल्प आय तथा कमजोर वर्ग के उस बड़े समूह को जो सामान्य रूप से प्रचलित बैंकिंग प्रणाली से बैंकिंग सेवा तथा लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। वहनीय लागत पर बैंकिंग सेवा में उपलब्ध कराना है।” अन्य शब्दों में वित्तीय समावेशन का अर्थ है, “अब तक वित्तीय सेवाओं व उत्पादों से वंचित रहे लोगों तक सुविधापूर्वक सरल तरीके से उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।” अर्थात् कम आय व कमजोर वर्ग के लिए सस्ती दरों पर ऋण व वित्तीय सेवाओं तक सुगमतापूर्वक पहुंच ही वित्तीय समावेशन है। अतः इसके अंतर्गत कम लागत पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वित्तीय समावेशन में ऐसे साधनों का विकास किया जाता है, जिससे कि गरीबी उन्मूलन किया जा सके। वैसे तो स्वतंत्रा भारत में वित्तीय समावेशन की शुरुआत 1949 आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के साथ की गई थी तथा 1969 व 1980 में क्रमशः 14 व 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन की अवधारणा विशेष रूप से उस समय अधिक प्रचलन में आयी जब 2005-06 के एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट में इस पर बल दिया गया कि सभी राज्यों में राज्य स्तर पर बैंकर समिति के प्रायोजक बैंक को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि अपने कार्य क्षेत्रों में कम से कम एक जिला 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन में आए।

अतः स्पष्ट है, “वित्तीय समावेशन एक आर्थिक व सामाजिक विकास है जो कम आय वाले ग्राहकों और संस्थानों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है।” आई.एल.ओ. वित्तीय समावेशन का तात्पर्य, “कमजोर आय वर्ग को निश्चित समय पर वित्तीय सहायता पहुंचाना है।” डॉ. सी. रंगराजन, चेयरमैन, ‘द कमिटी आफ

फाइनेंशियल इंकलूजन।' बरेली उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जिला है और इसमें वित्तीय समावेशन का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है।

परिचय— बरेली एक बड़ा जिला है जो लखनऊ से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी भारत की राजधानी दिल्ली से दूरी भी लगभग 250 किलोमीटर है। इसे नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके चारों दिशाओं में शिव जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। बरेली उत्तरी भारत का एक हिस्सा है। इतिहास में पांचाल क्षेत्रा के नाम से जाना जाता था जहां पर द्रौपदी का जन्म हुआ था। गौतम बुध ने भी बरेली के अहिच्छन्न क्षेत्रा में भ्रमण किया था। बरेली का नाम 1537ई0 में जगत सिंह कठेरिया राजपूत राजा के द्वारा रखा गया। बरेली लगभग 8500 किलोमीटर के क्षेत्रा में फैला है जहां की जनसंख्या लगभग 55 लाख है। बरेली में लगभग 70 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है। बरेली में मौसम सभी तरह का रहता है जैसे दिसंबर और जनवरी में मौसम ठंडा रहता है जब तापमान लगभग 8 डिग्री तक पहुंच जाता है और अप्रैल-मई में मौसम गर्म रहता है जहां तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसी तरह बरसात में खूब बरसात होती है। खेती के हिसाब से यहां किसान सामान्य तौर पर साल में दो बार फसल काटता है। बरेली में हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाएं बोली जाती है। बरेली शहर में बांस की लकड़ी से बने फर्नीचर और कॉटन बनाने का काम बहुतायत में होता है।

क्योंकि इस रिसर्च पेपर में हम बरेली जिले के बारे में अध्ययन कर रहे हैं अतः बरेली के आंकड़ों पर एक नजर डालना अति आवश्यक है। जनसंख्या के मामले में बरेली उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में से है। 2011 की जनगणना से हमें ज्ञात होता है कि बरेली की कुल जनसंख्या 4448359 थी जिसमें 2357665 पुरुष और 2090 694 महिलाएं शामिल थी। 2011 में यहां की साक्षरता दर 58.5 प्रतिशत थी जिसमें पुरुष 67.5 प्रतिशत और महिलाएं 48.3 प्रतिशत साक्षर थी। बरेली की लगभग 64 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में और लगभग 36 प्रतिशत आबादी शहरी इलाकों में रहती है।

वित्तीय समावेशन के मामले में बरेली में स्वाभिमान योजना के तहत यह बताया गया था कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक खाता होना चाहिए। क्योंकि बैंकिंग क्षेत्रा ही ऐसी कुंजी है जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। बैंकिंग क्षेत्रा के मामले में बरेली में बैंकिंग सेवाओं का फायदा उठा रहे परिवारों की संख्या लगभग 71 प्रतिशत है।

क्रिसिल इंकलूसिक्स

वित्तीय समावेशन की दर को नापने के लिए भारत सरकार द्वारा क्रिसिल इंकलूसिक्स सूचकांक तैयार किया गया। यह सांख्यिकी रूप से बहुत मजबूत होता है और समझने में आसान है। यह 0 से 100 की बीच में गणना करता है। यह किसी स्थान पर बैंकों की शाखाएं, बैंक में कुल जमा खाते, बैंक में कुल क्रेडिट और कुल बीमा धारको के आधार पर अपनी गणना करता है, और इस के नवीनतम संस्करण में जीवन बीमा के डाटा को भी शामिल किया गया है। इसी तरह 2013 में इसमें माइक्रो फाइनेंस डाटा को भी शामिल किया गया।

क्रम संख्या	सन्	क्रिसिल स्कोर	क्रिसिल रैंक
1	2016	45 ^ण 4	399

2	2015	44 ^प 8	385
3	2014	40 ^प 7	392
4	2013	38 ^प 6	414
5	2012	34 ^प 6	349
6	2011	33 ^प 4	322
7	2010	30 ^प 8	326
8	2009	29 ^प 1	314

क्रिसिल इंडेक्स के अनुसार किसी भी स्थान के वित्तीय समावेशन को क्रिसिल इंकलूजन द्वारा चार श्रेणियों में बांटा गया है—1. जिसमें 55 से ऊपर क्रिसिल इंकलूजन होने पर उच्च वित्तीय समावेशन को दिखाता है। 2. इसी तरह 40.1 से 55 के मध्य क्रिसिल इंकलूजन होने पर एवरेज से ऊपर वित्तीय समावेशन को दर्शाता है, 3. इसी तरह 20 से 40 के मध्य क्रिसिल इंकलूजन रहने पर एवरेज से नीचे वित्तीय समावेशन के स्तर को दर्शाता है 4. और 25 से नीचे क्रिसिल इंकलूजन रहने पर लो वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।

बरेली में वित्तीय समावेशन क्रिसिल इंडेक्स 2018 के अनुसार उपरोक्त तालिका से दर्शाया गया है— इस तालिका को देखने से पता चलता है कि 2010 में बरेली की क्रिसिल रैंक 314^{वीं} थी जो 2016 में 399 स्थान पर पहुंच गई जबकि क्रिसिल स्कोर 2010 में 30.8 था जो 2016 में 45.4 पहुंच गया अर्थात् बरेली में 2010 से बरेली में 2010 से 2016 के मध्य वित्तीय समावेशन की स्थिति में काफी सुधार हुआ परंतु बरेली की रैंक भारत के अन्य जिलों के सापेक्ष घटने से यह स्पष्ट है कि बरेली में वित्तीय समावेशन की स्थिति में उतना सुधार नहीं हुआ जितना की अन्य जिलों में हुआ क्योंकि सुधार के बावजूद भी बरेली की रैंक 2010 के मुकाबले 2016 में नीचे गिर गई है। इन आंकड़ों से यह पता लगता है कि बरेली में वित्तीय समावेशन के विकास के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

वित्तीय समावेशन को आमतौर पर गरीब जनता द्वारा बैंकिंग सेवाओं से जुड़ने को एवं बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने को समझा जाता है। वर्तमान अध्ययन में हम वित्तीय समावेशन के रास्ते में बरेली जिले में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करेंगे और बरेली जिले में वित्तीय समावेशन की स्थिति का अध्ययन करेंगे।

परिकल्पना

1. बरेली जिले कि गरीब आबादी तक वित्तीय समावेशन की बैंकिंग खातों की महत्वपूर्ण पहुंच है।
2. बरेली में गरीब आबादी तक वित्तीय समावेशन की बीमा योजनाओं की महत्वपूर्ण पहुंच नहीं है।

अनुसंधान विधि

वर्तमान रिसर्च पेपर में अनुसंधान विधि गुणात्मक अनुसंधान पद्धति पर निर्भर है। क्योंकि इसमें खोजपूर्ण और वर्णनात्मक विश्लेषण का उपयोग किया गया है। इसमें साक्षात्कार के जरिए वित्तीय समावेशन की स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है।

नमूना करण

बरेली की 6 तहसीलों से प्रत्येक तहसील में 200 लोगों से साक्षात्कार कर विस्तृत जानकारी ली गई और इस तरह पूरे जिले में 1200 लोगों द्वारा जानकारी इकट्ठा की गई है। नमूना लेने के लिए नमूना करण की क्लस्टर विधि का प्रयोग किया गया है।

डेटा संग्रह

आंकड़ों का संकलन प्राथमिक डाटा जोकि 12 सौ लोगों से साक्षात्कार विधि द्वारा इकट्ठा किया गया एवं द्वितीय डाटा जो की विभिन्न सरकारी आंकणों से प्राप्त किया गया है।

डाटा प्रोसेसिंग एवं विश्लेषण

प्राथमिक स्रोतों से इकट्ठा किए गए डाटा को सांख्यिकी विधियों द्वारा सारणीबद्ध और विश्लेषित किया गया और उसके अवलोकन पश्चात निष्कर्ष निकाला गया।

बरेली जिले में वित्तीय समावेशन की वास्तविक स्थिति— बरेली जिले में वित्तीय समावेशन की स्थिति की जांच करने के लिए उपरोक्त अनुसार प्राथमिक एवं द्वितीय डाटा का विश्लेषण किया गया जिससे निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए—

डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि 2011 में बरेली की कुल जनसंख्या 64.7 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहती थी परंतु 2021 में बरेली की कुल जनसंख्या का लगभग 62.5 प्रतिशत की ग्रामीण इलाकों में रहता है जिससे पता लगता है कि शहरों का विकास हुआ है अर्थात लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई है।

प्राप्त जानकारी के आधार पर यह ज्ञात होता है कि चयनित व्यक्तियों में से लगभग 22 प्रतिशत लोगों ने ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, जबकि लगभग 12.5 प्रतिशत लोगों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में और अटल पेंशन योजना में निवेश किया है, जबकि लगभग 32 प्रतिशत लोगों ने कोई भी योजना नहीं ली, क्योंकि अधिकांश लोगों को बीमा उत्पादों की जानकारी नहीं थी क्योंकि लगभग 33 प्रतिशत लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं है, इसीलिए उन लोगों को बीमा योजना की जानकारी नहीं मिली।

बरेली जिले का बैंकिंग पैठ अनुपात लगभग 33.50 प्राप्त हुआ। इसी तरह कर्ज से वंचित किए गए खेती हार परिवारों का अनुपात 82.91 प्रतिशत आया। इसी तरह निचले पायदान पर स्थित खाता धारको का अनुपात लगभग 33.5 प्रतिशत आया।

निष्कर्ष— उपरोक्त प्रथम एवं द्वितीय डाटा से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि बरेली के लोगों को उनकी बचत और निवेश की जरूरत के लिए बैंकिंग शाखाओं तक पहुंच अच्छी है, लगभग 71 प्रतिशत लोगों की बैंको तक पहुँच है, परंतु बीमा योजना के बारे में वे लोग अभी अच्छी

तरह से परिचित नहीं है इसीलिए उनका ठीक प्रकार लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यह बीमा योजनाएँ सुरक्षा हेतु परम आवश्यक है।

सुझाव – यह सुझाव दिया जाता है कि बरेली में लोगों के बीच बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और उसके लाभ उठाने के बारे में उन्हें जागरूक करना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देनी चाहिए और उन्हें जन धन योजना में ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने की जानकारी भी देनी चाहिए। जैसे और कर्मचारी संगठनों में भविष्य निधि योजना पेंशन योजना के अंतर्गत चलाई जाती है उसी तरह अटल पेंशन योजना में भी यही सुविधा दी जाए। बीमा योजनाओं का आकर्षक न होना भी इनकी व्यापकता को कमजोर करता है इसलिए आकर्षक बीमा योजनाएं लाई जानी चाहिए और उसकी जानकारी जन-जन तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। बरेली जिले में साक्षरता दर बहुत कम है अतः बरेली में साक्षरता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो।

संदर्भ

- [1] Adrian Alter & Boriana Yontcheva, 2015. “Financial Inclusion and Development in the CEMAC,” IMF Working Papers 15/235, International Monetary Fund.
- [2] Arora S. (2012). Microfinance interventions and customer perceptions: a study of rural poor in Punjab 39(1).
- [3] Balaji T.P (2017) Impact of Financial Inclusion on Socioeconomic Condition of Weaker Section of the Society, thesis submitted to University of Madras, Chennai.
- [4] Banerjee G. and Banerji S. (2016). The Economics of Financial Inclusion, a book published by Ane Book Pvt Ltd, New Delhi.
- [5] Bapat D. and Bhattacharyay B. N. (2016). Determinants of Financial Inclusion of Urban Poor in India: An Empirical Analysis, Series/Report no, CESifo Working Paper 6096.
- [6] Bhandari Geetika. (2020). Quantitative Study Of Regional Disparity For Financial Inclusion Among The Districts Of Rajasthan, Mohan Lal Sukhadia University.
- [7] Prasad K.V.S and Rao G. (2012). Performance Appraisal of Andhra Bank and its role in Financial Inclusion, International Journal of Languages, Education and Social Sciences, 3(1)
- [8] Qureshi S. and Trehan K. (2014). Role of Financial Inclusion in Restraining Entrepreneurial Breakdown In India, International Journal Of Core Engineering & Management(IJCEM), 1(1).

- [9] Raghuram Rajan, (2015) Democracy, Inclusion, and Prosperity, the D. D. Kosambi Ideas Festival, Goa, February 20, 2015, Available at: <https://rbi.org.in/SCRIPTS/BSSpeechesView.aspx?id=941s>
- [10] Crisil Index 2018.
- [11] RBI Data.
- [12] History of Bareilly